कोटद्वार, गुरूवार
1 अगस्त 2024
वर्षः 46
अंकः 98 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

नो पार्किंग में खड़ी 24 टैक्सियों के मसूरी प्रवेश पर रोक लगाई

देहरादून। उपजिला अधिकारी डॉ. दीपक सैनी ने लंढौर रोड और नगर पालिका रोड पर अवैध रूप से खड़ी किए जाने वाली टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई की। इन 24 टैक्सियों के मसूरी प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने एसडीएम को बताया कि पिक्चर पैलेस से लंढौर रोड और नगर पालिका रोड के किनारे अवैध रूप से टैक्सियां खडी होने से पर्यटकों व स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। यातायात बाधित होता है। जिस पर एसडीएम ने निरीक्षण किया और पाया कि इन स्थानों पर टैक्सियां खड़ी हैं। जिस पर उन्होंने अध्यक्ष टैक्सी यूनियन को भी लिखित के साथ मौखिक रूप से अवगत कराया, इसके बाद भी आदेशों का उलंघन किया गया। इस मसूरी कोतवाल की रिपोर्ट और मसूरी में यातायात व्यवस्था का बनाए रखने के लिए नियम तोड़ने वाली 24 टैक्सी वाहनों के मसूरी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके कोल्हूखेत बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को दिए गए हैं। ताकि इन नंबर की टैक्सी मसूरी आती हैं तो उन्हें वहीं पर रोककर वापस लौटा दिया जाए।

सरकारी रिकार्ड फाड़कर जमीनों के मालिक बदले गए

देहरादून। राजस्व विभाग में जमीनों का सरकारी रिकार्ड फाड़कर फर्जीवाड़ा किया गया। कुछ जमीन जिन लोगों के नाम दर्ज कर दी गई, उनके नाम दर्ज किए जाने की आदेश की पत्रावलियां गायब हैं। जमीन रायपुर क्षेत्र की हैं। मामले में देहरादून सदर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है।शहर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जानबूझकर बेमानी से कपट करने के आशय से राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों में छेड़छाड़ की। फसली वर्ष 1376 से जुड़ी आर–6 पंजिका (वर्ष 1956 से 1975) का पृष्ठ फाड़ दिया गया। इसका तहसील के रिकार्ड से मिलान कराने पर वहां मिसलबंद पंजिका गायब मिली। इसके अलावा फसली वर्ष 1373 से 1378 को ग्राम रायपुर की खतौनी में आदेश सुपरवाइजर कानूनगो पेज क्रमांक 11 के क्रमांक 3/31–12–1991 में मृतक गोर्वधन पुत्र सालक का नाम खारिज करके महेश्वरानंद, दयानंद, पूर्णानंद, ज्योति प्रसाद, मोहनलाल पुत्र गोवर्धन का नाम बतौर वारिस दर्ज हैं। इस आदेश से संबंधित अभिलेख तहसील अभिलेखागार में मौजूद नहीं हैं। प्रशासन ने माना कि अभिलेखों में छेड़छाड़ का प्रकरण लंबी अवधि का है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह फर्जीवाड़ा किसने किया है। मामले में देहरादून सदर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेम प्रकाश गोस्वामी की तहरीर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर कोतवाली चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि मामले में अभिलेखों में गड़बड़ी की जांच में वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा।

सात वर्षीय किशोर से कुकर्म के दोषी को बीस साल की सजा

देहरादून। सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही पीड़ित को अपराध पीड़ित योजना से दो लाख रुपये की सहायता दिलाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं।

दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना चार मार्च 2020 को कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। बालक की मां ने पुलिस को बताया था कि उनका सात वर्षीय बेटा घर में अकेला था। वह जब घर आई तो बेटा अंदर कमरे में था और उसके बेड पर कुछ निशान लगे हुए थे। उसके निजी अंगों पर भी निशान थे। मां ने बेटे से पूछा तो उसने बताया कि किराएदार सुनील निवासी ग्राम चांदनी, त्यूनी ने उसके साथ गलत काम किया है।

सात जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

देहरादून। उत्तराखंड के कुछ जिलों में अगले दो दिन मानसून की वर्षा भारी पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, आज सात जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसे देखते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में कहीं–कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अन्य जिलों में कहीं–कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की आशंका है। यह क्रम दो दिन बना रह सकता है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए देहरादून समेत पांच जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में बुधवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है।

अचानक छा गया अंधेरा

वहीं बुधवार को दोपहर बाद देहरादून और हल्द्वानी में अचानक अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो शाम हो गई हो। लोग वाहनों की लाइट जलाकर सड़क पर वाहन चलाते दिखे। वहीं बुधवार तड़के से हल्द्वानी में बारिश का दौर जारी रहा।

धूप और बादलों की आंख–मिचौनी

मंगलवार को सुबह से दून समेत आसपास के क्षेत्रों में धूप और बादलों की आंख–मिचौनी जारी रही। इस बीच हल्की बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। हालांकि, इस दौरान तापमान सोमवार की तुलना में कम रहा, लेकिन उमसभरी गर्मी बनी रही।

रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को मिलेगी एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी

देहरादून रिटायरमेंट पर अब कर्मचारियों को एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी। जनवरी 2024 से यह लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने मंगलवार को इसके आदेश किए। दरअसल, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी किए जाने के आधार पर केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम के तहत ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड वेतन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया। राज्य कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को यह लाभ मिलेगा। इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो आश्रित को यह राशि मिलेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी इससे ज्यादा बनती है तो इस दशा में भी अधिकतम 25 लाख की ग्रेच्युटी का भुगतान होगा।

योजनाओं के क्रियान्वयन में हो विज्ञान एवं तकनीकि का उपयोग:मुख्यमंत्री

● सहकारिता की जन कल्याणकारी योजनायें बने गेम चेंजर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि लंबे समय से संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इस दिशा में सुधारात्मक प्रयास की दिशा में कार्य किये जाएं। इन योजनाओं से लाभार्थियों को कितना फायदा हुआ और योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए और क्या विशेष नवाचार किये जा सकते हैं, इस दिशा में नियोजन विभाग के सहयोग से कार्य किया जाए। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गेम चेंजर बनाने की दिशा में कार्य किये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किये जा रहे ऋण की धनराशि की सीमा में वृद्धि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव लाया जाए। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिए सप्लाई चेन को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा सहकारिता विभाग संबधित विभागों से भी समन्वय स्थापित कर योजनाओं को आगे बढ़ाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंजर भूमि चिन्हित कर विभिन्न क्लस्टरों के माध्यम से उसे खेती योग्य बनाने के प्रयास किये जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक और पारम्परिक पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने क्लस्टरों में मिल्लेट्स, सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों फसलों, चारा फसलों और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान कर, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। सहकारिता से मिलेट्स उत्पादों को और अधिक बढ़ावा मिले, इसके भी पयास किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न जनपदों में चयनित क्लस्टरों की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत मत्स्य पालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया दिया जाए।

आपदा को लेकर दी गई चेतावनी, केरल सरकार ने नजरअंदाज की

● वायनाड भूस्खलन को लेकर बोले गृह मंत्री

नईदिल्ली, केरल के वायनाड में आई तबाही में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वॉर्निंग दी गई है। चेतावनी देने के बावजूद केरल सरकार ने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई और इसमें लापरवाही बरती। इस घटना को लेकर मिली चेतावनी के बाद भी केरल सरकार ने लोगों को वहां से नहीं हटाया। केरल सरकार ने केंद्र की चेतावनी के नजरअंदाज किया।

अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, मैं कुछ चीजों की स्पष्टता के लिए खड़ा हुआ है। इस घटना में जितने लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मृतकों के परिजनों और उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी अपार संवेदना है। जानकारी के अभाव में कुछ टिप्पणियां हुई। देश के सामने कोई गलतफहमी न जाए इसलिए मैं स्पष्टता देना चाहता हूं। अंग्रेजी में अर्ली वॉर्नंग–अर्ली वॉर्निंग विपक्ष द्वारा बोला ही गया। 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की तरफ से अर्ली वॉर्निंग दी गई थी। इसके बाद 24, 25 और 26 जुलाई को वॉर्निंग दी गई।उन्होंने कहा कि सभी चेतावनियों में कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, भारी वर्षा होगी और लैंडस्लाइड की संभावना है, जिसकी चपेट में आकर लोग मर सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन भारत सरकार की वॉर्निंग प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस वॉर्निंग सिस्टम का उपयोग कर जीरो कैजुअलटी देखा है। गुजरात सरकार और ओडिशा सरकार ने इस प्रणाली का इस्तेमाल किया। गुजरात में तो इस वॉर्निंग सिस्टम के कारण एक पशु तक नहीं मरा। भारत सरकार ने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्ची किया है।

घोटाले का आरोप लगाने वाले पर 25 लाख मानहानि का भेजा नोटिस

देहरादून। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी को लगाये गये झूठे आरोपों के खिलाफ 25 लाख का मानहानि का कानूनी नोटिस दिया है। जिसका जवाब आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि प्रदीप भंडारी ने गलत आरोप मीडिया में लगाकर मेरी छवि का धूमिल किया है, जिसके कारण मानहानि का नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदीप भंडारी ने झडीपानी गौशाला में 75 लाख के घोटाले का आरोप लगाया है, जबकि नगर पालिका बोर्ड में गौशाला निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है जिसे शासन को भेजा गया। शासन ने 49 लाख 50 की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसका ई टेंडर 17 अक्टूबर 2020 को लगाया गया। जिसके बनने के बाद एक और ई टेंडर 16 अगस्त 2022 को गौशाला के बचे कार्य और ऊपर 10 कमरे बनाने का किया गया। दोनो टेंडर जब हुए तब तक उनकी पोस्टिंग नगर पालिका में नहीं हुई थी।

माहौल पक्ष में होने का विधानसभा चुनाव में मिलेगा फायदा : सोनिया

नई दिल्ली , कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से माहौल कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के पक्ष में है, इसलिए जिन राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है, वहां इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है। श्रीमती गांधी ने संसद भवन परिसर में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के बाहर और भीतर कांग्रेस अपने संदेश देने में पूरी तरह सफल हो रही है और प्रभावी तरीके से अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रही है।

उन्होंने कहा कि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, उन्हें भी प्रभावित तरीके से हर जगह पार्टी का संदेश पहुंचाना है और कांग्रेस को मिलकर सबको मजबूती से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह तब ही संभव हो सकता है, जब हम मजबूती से संसद तथा संसद के बाहर अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे।

उन्होंने सरकार पर किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन से न्याय नहीं किया जा रहा है। सरकार बजट को लेकर बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सच यह है कि बजट को लेकर व्यापक निराशा है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और देश का आम नागरिक सरकार पर भरोसा नहीं कर रहा है, जबकि पूरा सरकारी तंत्र देश की जनता को भरमाने में लगा हुआ। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों में सीट कम होने से सबक लेगी, लेकिन वह अब भी समुदायों को विभाजित करने और भय तथा शत्रुता का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम हैं।

अच्छा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह अस्थायी राहत है। नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को बदल दिया गया है।

आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। कांग्रेस नेता ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। देश को आगे ले जाने की बजाय पूरी शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लाखों युवाओं का विश्वास टूट गया है और उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है।

दिल्ली में कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा, आप सरकार लाएगी कानून

नईदिल्ली,दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत के मामले पर सडक़ से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार कोचिंग सेंटर विनियमन कानून के जरिए कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।बुधवार को कैबिनेट मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए जल्द ही कानून आएगा।आतिशी ने पत्रकारों को बताया कि कानून तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न कोचिंग सेंटर के छात्रों की मदद ली जाएगी।उन्होंने बताया कि अधिकारियों और छात्रों की समिति कानून के प्रावधानों पर चर्चा करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, शिक्षकों की योग्यता, फीस विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे।मेयर ने बताया कि इसमें जनता की राय भी ली जाएगी। कानून को दिल्ली सरकार द्वार पास करने के बाद नगर निगम इसका पालन करेगा।

27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बने पुस्तकालय में भारी बारिश के बाद पानी घर गया था। इस दौरान यहां फंसे 35 छात्रों में 3 की डूबने से मौत हो गई। मृतकों केरल के नेविन डाल्विन, तेलंगाना की तान्या सोनी और उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव हैं।मामले में अब तक कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक समेत 7 गिरफ्तार किए गए हैं।

बदरीनाथ हाईवे बार–बार बाधित होने से कारोबारी परेशान

चमोली। बुधवार को बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नन्दप्रयाग में 8 घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा। मलबा आने के कारण नन्दप्रयाग बाजार से आगे सुबह 5 बजे पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर आने के कारण दो स्थानों पर अवरुद्ध रहा। सड़क पूरी तरह दलदल में बदल गई है।

वाहनों का दलदल से निकलना मुश्किल हो रहा है। भारी मशक्कत के बाद मशीनों से हाइवे को दोपहर 1 बजे तक सुचारू काया गया। बदरीनाथ हाइवे चमोली कस्बे के निकट बाजपुर मे भी मलबा बोल्डर आने से हाईवे 5 घंटे अवरुद्ध रहा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्दकिशोर जोशी ने बताया कि बदरीनाथ हाईवे बुधवार अपराह्न बाद सामान्य तौर पर यातायात के लिए सुचारू किया गया। बदरीनाथ हाइवे चमोली जिले में इस बार बरसात में फिर मुसीबत की सड़क साबित हो रही है।

बायोमेट्रिक से जीएसटी पंजीकरण वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड

–वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया शुभारंभ

देहरादून। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को लक्ष्मी रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इस व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित हुई जीएसटी परिषद की बैठक में पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत गुजरात, पुद्दुचेरी तथा आंध्रप्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली से ऐसे पंजीकरण आवेदन पत्रों को पकड़ा जा सकता है जिसमें गड़बड़ी की आशंका होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर जोखिम वाले पंजीकरणों की जांच की जाएगी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन इस प्रमाणी से किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि गुजरात में इस प्रणाली के लागू होने के बाद पंजीकरण आवेदनों में 55% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि फर्जी पंजीकरण आवेदनों की संख्या कम हुई है।

150 करोड़ तक की कर चोरी रुकेगी

अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि राज्य में इस नई व्यवस्था के लागू होने से सालाना 100 से 150 करोड़ तक की कर चोरी को पकड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जीएसटी की आसान पंजीकरण प्रक्रिया का गलत लाभ उठाते हुए फर्जी पंजीकरण करा रहे हैं। इससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था से जीएसटी में पंजीकरण प्रक्रिया बेहतर होगी। जिससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए पंजीकरण पकड़ में आएंगे और कर चोरी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग टेंपो, रिक्शा, ठेली, फड़ वालों के आधार पर पंजीकरण लेकर जीएसटी की चोरी कर रहे थे। लेकिन बायोमैट्रिक प्रणाली के बाद इसे पकड़ा जा सकेगा।

जीएसटी के हर कार्यालय में खुलेगा सुविधा केंद्र

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य कर विभाग के प्रत्येक कार्यालय भवन में जीएसटी सुविधा केंद्र खोला जाएगा।

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर हटाया जाए जीएसटी

नितिन गडकरी की वित्त मंत्री सीतारमण से अपील

नईदिल्ली ,केंद्रीय सडक़ परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18त्न जीएसटी को हटाने का अनुरोध किया है।

गडकरी ने वित्त मंत्री सीतारमण से अपील करते हुए कहा है कि यह टैक्स जीवन की अनिश्चितताओं का बोझ डालता है और इससे इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ में भी दिक्कतें आती है। गडकरी ने 28 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कहा, आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है।लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी रेट वर्तमान में 18 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि यदि आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम 10 हजार रुपये है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो 1800 रुपये बनता है।पत्र में आगे कहा गया है, इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस सेक्टर या इंडस्ट्री की ग्रोथ में बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है।

बता दें कि इस पत्र में नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में बात रखी गई थी। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के सामने आने वाले मुद्दों को मोटे तौर पर बताये हुए एक ज्ञापन पेश किया गया था।

ज्ञापन का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उस पर इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।

झुग्गी झोपड़ी में आग लगने से बड़ा हादसा, 3 बच्चियों की मौत

नोएडा, दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार तडक़े बड़ा हादसा हो गया। यहां सेक्टर–8 स्थित फेज वन इलाके में एक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे 3 बच्चियों की मौत हुई है।पुलिस ने बताया कि घटना के समय तीनों बच्चियां अपने माता–पिता के साथ झोपड़ी में सो रही थी। तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उन्हें भागने का मौका नहीं मिला।माता–पिता की हालत गंभीर है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बच्चियों की पहचान 10 वर्षीय आस्था, 7 वर्षीय नैना और 5 वर्षीय आराध्या के रूप में हुई है। बच्चियों के पिता ई–रिक्शा चलाते थे।स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिता ने मंगलवार रात रिक्शा की बैटरी चार्ज करने को लगाई थी और पूरा परिवार एक कमरे में सो गया। तडक़े 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो कोई समझ नहीं पाया।आग तेजी से फैली, जिससे कमरे में सो रही बच्चियों की मौत हो गई और माता–पिता झुलस गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया।

दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों को पुलिस ने प्रदर्शन से रोका, हटाए बैनर पोस्टर

नई दिल्ली ,यूपीएससी छात्रों की मौत को लेकर राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस अपने साथ बस में बैठाकर दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों से बात करने ले गई है। इनके समक्ष छात्र अपनी बात रखेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें पुलिस बस में बैठाकर ले जा रही है। छात्रों ने कहा कि हम अपने साथी छात्रों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमें विरोध–प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड लगा दिए हैं, ताकि छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जाए। पुलिस से पूछा गया कि आप छात्रों को प्रदर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिला है। इस बीच कई छात्रों ने संतुष्टि जाहिर की है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए उच्च अधिकारियों के पास ले जाया जा रहा है, जहां वो अपनी बात रख सकेंगे।

अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्रों ने नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

संपादकीय

आफत का मानसून

उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है और अभी भी जहां एक तरफ चार धाम यात्रा चल रही है तो वहीं दूसरी ओर डाक कावड़ की भीड़ से हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश तक रास्ते जाम है। उत्तराखंड में बारिश के कारण भारी दिक्कत है सामने आ रही है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई मकान दब चुके हैं जबकि अनेकों स्थान पर या तो रास्ते बह गए या फिर उनमें मलबा आने के कारण परिवहन व्यवस्था ठप्प हो गई है। उत्तराखंड का एक बड़ा क्षेत्र पहाड़ों की भौगोलिक विषम परिस्थितियों से युक्त है जहां राहत कार्य चलाना बेहद जटिल व्यवस्था है। बावजूद इसके आपदा राहत तंत्र बरसात के समय होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करती है, लेकिन अब यह सरकारी प्रयास भी कमतर साबित हो रहे हैं। भारी बरसात के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया जाना था कि ऐसे स्थान चिन्हित जाते जाए जो भारी बारिश के कारण प्रभावित हो सकते हैं। इसके तहत जिला स्तर पर नदी नालों के किनारे बसे लोगों को चेतावनी दी जाती है तो वही पहाड़ी क्षेत्रों में भी यात्रा करने वालों को सतर्कता बरतने के साथ-साथ बेहद जरूरी न होने पर यात्रा को स्थगित करने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि बारिश के दौरान व्यवस्थाओं के बिगड़ने का एक बड़ा करण सरकारी व्यवस्थाएं भी है जो मानसून से पूर्व पर कार्य नही करती। हरिद्वार का ही प्रकरण देखें जहां पिछले दिनों सूखी नदी पर एकाएक आई बाढ़ के कारण कई वाहन बह गए थे और इधर कांवड़ियों का एक ट्रक पुनः सूखी नदी पर पार्किंग में खड़ा था जो भारी बारिश के बाद देखते ही देखते बह गया। पूर्व में हुए बड़े हादसे के बाद प्रशासन को यहां पार्किंग व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए थी लेकिन बड़े हादसे के बावजूद यहां वाहन खड़े कर दिए गए। यूं तो प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है लेकिन कुछ प्रयासों से ऐसे हादसों पर नियंत्रण या फिर इन हादसों के कारण होने वाली जान माल की हानि को जरूर कम किया जा सकता है। नगरीय व्यवस्थाओं का हाल तो इस मानसून में सामने आ ही चुका है तो वही पहाड़ों में भी स्थिति लगातार बारिश के कारण अब बेहद विकराल होती चली जा रही है। अभी भी मानसून के थमने की उम्मीद अगले कुछ और दिन नहीं है और इन परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ मानसून के थमने की प्रतीक्षा करना ही सबसे बेहतर विकल्प नजर आ रहा है।

जल-संकट का हाहाकार

भारत डोगरा

हाल के विकास कार्यक्रमों में हर घर जल की योजना विशेष तौर पर चर्चित रही है, विशेषकर दूर-दूर के गांवों के संदर्भ में। इन गांवों के परिवारों और विशेषकर महिलाओं के समय का एक बड़ा भाग परिवार की पानी की जरूरतों को पूरा करने में ही जाता रहा है।

दिन भर प्रयास करने के बाद भी कई बार पानी जैसी बुनियादी जरूरत की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती थी और गर्मी के दिनों में तो जैसे जल-संकट का हाहाकार ही मच जाता था।

इस स्थिति में जब भारत सरकार ने हर घर में नल का जल पंहुचाने की समयबद्ध योजना आरंभ की तो स्वाभाविक ही था कि इस योजना से बहुत उम्मीदें जुड़ गई। आज स्थिति यह है कि कहीं इस जल जीवन मिशन की उपलब्धि का उत्साह है तो कहीं अनेक समस्याओं को लेकर चिंता भी है। उपलब्धि और कठिनाइयों के बीच गांव किस स्थिति में है, यह जानने के लिए इन पंक्तियों के लेखक ने हाल में निवाड़ी जिले (मध्य प्रदेश) के अनेक गांवों का दौरा किया।

यह बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेषकर गर्मियों के दिनों में, जल-संकट के लिए चर्चा में रहा है। यह सन्रेक्षण भीषण गर्मी के दिनों में किया गया और मौसम सुधरने पर इससे बेहतर स्थिति सामने आएगी। इस क्षेत्र में सुखद स्थिति यह है कि गांव-स्तर की जल समितियों के स्तर पर अनेक गांववासी खुल कर अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में परमार्थ संस्था ने 'जल सहेली' महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से जल के मुद्दे पर जागरूकता फैलाई है और ग्राम सभाओं तथा पंचायतों में भी उनके विचारों को अधिक महत्त्व मिलने लगा है। इस तरह पानी के मुद्दे पर जनसक्रियता बढ़ी है और लोगों की समस्याओं के समाधान की संभावना बढ़ी है। जल-जीवन मिशन के अंतर्गत जब पाइपलाइनों को बिछाया गया, नल लगाए गए तो इस जागरूकता के कारण लोग बेहतर ढंग से गलतियों को रोक सके और स्थानीय ज्ञान के आधार पर बेहतर व्यवस्था कर सके।

बहेरा गांव में यह सक्रियता अधिक है और अधिकांश परिवारों के नल लग गए हैं, पानी भी पहुंचने लगा है, फिर भी लगभग 12 प्रतिशत घरों में अभी पानी आना शेष है। ऊंचाई में पानी पंहुचाने में कठिनाई है, और स्कूल में भी। स्कूल के बोर में पानी गर्मी के चरम के दिनों में समाप्त हो गया और पास के एक अन्य कुएं में भी समाप्त हो गया। जिन गांवों में पानी आता है, सुबह आधे घंटे आता है। भीषण गर्मी के कारण यह गर्म होता है और पिया नहीं जाता। अतः पीने के लिए अनेक परिवार इस समय भी कुएं या हैंडपंप से ही पानी लाते हैं। नामापुरा गांव में अधिकांश घरों में पानी पहुंच रहा है पर ऊंचाई वाली बस्ती में अभी नहीं पहुंचा है। यहां पानी ले जाने के लिए तैयारी चल रही है।दो परिवारों ने कहा कि उनके नल भी नहीं लगे क्योंकि उनके घर पाइपलाइन की राह से कुछ हट कर हैं। नामापुरा गांव में नल में जो पानी आ रहा

दो परिवारों ने कहा कि उनके नल भी नहीं लगे क्योंकि उनके घर पाइपलाइन की राह से कुछ हट कर हैं। नामापुरा गांव में नल में जो पानी आ रहा है, वह स्वच्छ नहीं है और लोग इसे पीने के लिए उपयोग में नहीं लाते। वे योजना बना रहे हैं कि टंकी संचालक के पास जाकर पता लगाएं कि गंदा पानी क्यों भेजा जा रहा है। इस तरह गांव अभी पहले के स्रेतों पर ही पेयजल के लिए आश्रित हैं पर इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि इस पानी को पीने से पथरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। गांववासियों ने बताया कि पांच-छह लोगों का पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। पथरी से जुड़े दर्द और परेशानी की शिकायतें तो इससे कहीं अधिक लोगों को है और डॉक्टरों ने बताया है कि पानी के दूषित होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब आगे गांव को तैयारी यह करनी है कि कम से कम नई पाइपलाइन का पानी स्वच्छ मिले जिससे वे पेयजल की आवश्यकताएं इससे पूरी कर सकें।

है, वह स्वच्छ नहीं है और लोग इसे पीने के लिए उपयोग में नहीं लाते। वे योजना बना रहे हैं कि टंकी संचालक के पास जाकर पता लगाएं कि गंदा पानी क्यों भेजा जा रहा है। इस तरह गांव अभी पहले के स्रेतों पर ही पेयजल के लिए आश्रित हैं पर इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि इस पानी को पीने से पथरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। गांववासियों ने बताया कि पांच-छह लोगों का पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। पथरी से जुड़े दर्द और परेशानी की शिकायतें तो इससे कहीं अधिक लोगों को है और डॉक्टरों ने बताया है कि पानी के दूषित होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब आगे गांव को तैयारी यह करनी है कि कम से कम नई पाइपलाइन का पानी स्वच्छ मिले जिससे वे पेयजल की आवश्यकताएं इससे पूरी कर सकें।चुरारा गांव में विभिन्न मुहल्लों में स्थिति भिन्न है जहां दलित, आदिवासी और कुशवाहा मोहल्लों में अधिक समस्याएं हैं। कुछ कुशवाहा परिवारों ने नल को उतार दिया है क्योंकि उनके अनुसार जब पानी ही नहीं आ रहा है तो इसे क्यों रखें पर कुछ अन्य मोहल्लों में स्थिति बेहतर है। कुछ लोगों ने कहा कि गर्म पानी पिया नहीं जाता। पहले मटके में रखना पड़ता है। फिर बाद में पी सकते हैं। पानी रोज नहीं आता है।

सेन्री गांव में दो दलित मोहल्लों में अभी पाइपलाइन और नल पहुंचे ही नहीं हैं। अन्य मोहल्लों में जहां नल लग गए हैं, वहां पानी रोज नहीं आता है और जब आता है तो उसका समय निश्चित नहीं होता। आदिवासी (सहरिया) मोहल्ले और साईबाबा मोहल्ले में पानी की अधिक कठिनाई है। कुछ अन्य स्थानों में लोगों को बोर और हैंडपंप से आपूर्ति हो जाती है। अतः वे पाइपलाइन के पानी के बारे में विशेष चिंतित नहीं हैं। जहां तक परंपरागत कुओं का सवाल है तो वे लगभग बंद हो चुके हैं। एक समय इन कुओं की गांव की पेयजल आपूर्ति में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका थी पर जिस तरह ये निरंतर उपेक्षित होते रहे तो अब इनकी भूमिका जल आपूर्ति में नगण्य हो गई है।इस तरह जहां कुछ स्रेत बढ़ रहे हैं तो कुछ कम भी हो रहे हैं। नामापुरा गांव के लोगों ने बताया कि पहले हरियाली बहुत अधिक थी, पेड़ बहुत अधिक थे। इनके बहुत कम हो जाने से जल संरक्षण पर और गर्मी का प्रकोप बढने पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर जल-स्तर तेजी से नीचे गया है। एक ही गांव जैसे सेन्री में एक मोहल्ले की अपेक्षा दूसरे मुहल्ले में जल-स्तर बहुत नीचे हो सकता है और जहां यह बहुत नीचे है वहां बोर विफल हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। अधिक कठिनाई उन गांववासियों की है जहां बोर विफल हैं, जल-स्तर नीचे चला गया है और अभी पाइपलाइन का पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा है।

इस तरह की अनेक कठिनाइयों के बावजूद कुछ स्थानों पर यह उत्साह है कि कम से कम नल और पाइपलाइन तो आ ही गए हैं और गर्मी का प्रकोप कम होने के बाद स्थिति सुधरेगी तो नल में पानी भी बेहतर और अधिक मिलेगा। इस स्थिति में जिन महिलाओं को दिन भर पानी के लिए खटना पड़ता था, उससे मुक्ति मिलेगी। बहेरा की एक महिला ने कहा कि पहले कभी रिश्तेदारी में जाते थे, उस समय भी यही चिंता लगी रहती थी कि गांव लौट कर पहले पानी लाना है, तभी आराम कर सकेंगे या कुछ और काम कर सकेंगे। अब ऐसी स्थिति से राहत मिलेगी। इस तरह अपने इस आरंभिक दौर में हर घर जल योजना उपलब्धियों और कठिनाइयों के मिले-जुले दौर से गुजर रही हैं। अभी तक जो अनुभव सामने आए हैं, उनका सही आकलन कर उनसे सीखना जरूरी है ताकि भविष्य में जल जीवन मिशन का और सुधरा हुआ रूप लोगों को और भी राहत देने में सफल हो सके।

आरक्षण भारतीय राजनीति की धुरी

डॉ. आशुतोष कुमार

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान में आरक्षण के प्रावधान को शामिल किया था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आरक्षण एक समय भारतीय राजनीति की धुरी बनकर राजनेताओं के लिए एक ऐसा अमोघ मंत्र बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल किसी के कल्याण के लिए कम और किसी को परास्त करने के लिए ज्यादा किया जाएगा।आज आरक्षण के पीछे किसी पिछड़े या वंचित समाज के कल्याण की भावना कम और राजनीतिक स्वार्थ अधिक दिखती है।

सही मायने में आज आरक्षण राजनीति का झुनझुना बन गया है, जिसे चुनाव जैसे विशेष मौकों पर जनता को रिझाने के लिए बजाया जाता है।बहरहाल, आरक्षण एक बार फिर चर्चा में है। आरक्षण को लेकर चर्चा के केंद्र बिंदु में है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पहले एक पोस्ट की थी, जिसे बाद में उन्होंने हटा लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50 प्रतिशत और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी।सिद्धारमैया ने पोस्ट में कहा था, 'हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपनी जमीन पर आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। उन्हें कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित होने से बचाया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नडिगास के कल्याण की देखभाल करना है। जब उनके इस पोस्ट पर इस पर हर तरफ छीछालेदर होने लगा। विरोध में प्रतिक्रियाएं आने लगीं, तो दो दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर से पिछली पोस्ट हो हटाकर उसमें बदलाव कर दिया।

कर्नाटक सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी, लेकिन यहां मौजू सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है?कहीं आरक्षण की आड़ में देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? अगर नहीं, तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश की एकजुटता और अखंडता पर प्रहार क्यों किया जा रहा है। आमतौर पर इस तरह की कोशिश क्षेत्रीय दल की सरकार में की जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने को उस राज्य के प्रति ज्यादा उत्तरदायी समझते हैं, जहां उनकी सरकार होती है। हालांकि इस तरह की सोच भी देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक है। फिलवक्त कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर सिद्धारमैया सरकार ने ऐसी संकीर्ण मानसिकता क्यों दिखाई। जाहिर तौर पर इससे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन यहां चिंता का विषय कांग्रेस का नुकसान नहीं, अपितु राष्ट्र का और देश के संघीय ढांचे के नुकसान को लेकर है।अगर सभी राज्य सरकारें अपनी मर्जी की मालिक हो जाएंगी, तब तो देश का स्वरूप ही बिखर जाएगा। देश है, देश का एक स्वरूप है, उसकी अस्मिता है, तभी आरक्षण है। यह कहना ग़लत न होगा कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी, मगर समय के साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गई और अब तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आरक्षण की आंच देश की संघीय व्यवस्था पर भी आने लगी है। किसी राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए देश के स्वरूप और उसके संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। यह सहज ही समझा जा सकता है कि जब सभी राज्य सिर्फ अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी देने लगेंगे। वहां के प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ उसी राज्य के लोगों को रखा जाने लगेगा, तब भारत एक संघ रह जाएगा क्या? इसलिए राजनीतिक दलों और राज्य की सरकारों को यह जरूर सोचना होगा कि वे अपने प्रदेश के विकास की बात जरूर सोचें, प्रयास जरूर करें कि प्रदेश के लोगों को अपने ही राज्य में रोजी-रोजगार मिले, किंतु इसका भी ख्याल रखें कि देश की समावेशी संस्कृति को नुकसान न पहुंचे।

क्या कहता है भारतीय संविधान

भारतीय संविधान के भाग तीन में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वहीं, अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वगरे को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। वहीं, अनुच्छेद 16(4 ए) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती हैं, यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन इन सबके पीछे संविधान ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं देता जिससे देश की अस्मिता, एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो।

दुकानदारों के नाम सार्वजनिक समाज में मतभेद पैदा

कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दो जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि खाना बेचने वालों को यह बताना जरूरी है कि वे किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उस पर मालिक या कर्मचारियों का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता। पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि आदेश का अनुपालन स्वैच्छिक है, लेकिन इसे बलपूर्वक लागू किया जा रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा इसकी निंदा की गई तथा इसे विभाजनकारी कदम बताया। इस आदेश से समानता के अधिकार, अस्पृश्यता, भेदभाव का निषेध तथा कोई भी व्यापार करने के अधिकार का हनन कहा गया। वषों से चली आ रही यात्रा पर पहले कभी इस तरह के कोई आदेश नहीं जारी किए जाते रहे हैं।

कांवड़ मार्ग में आने वाले ढाबे/रेहड़ी स्वयं प्रचार करते हैं कि उनके यहां शुद्ध वैष्णव भोजन मिलता है। दूसरे फूड सेफ्टी एंड स्टैंर्डड एक्ट (एफएसएसएआई) व स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जैसे कानून पहले ही मौजूद हैं। जो खाद्य पदाथरे की गुणवत्ता सुनिश्चत करने का काम करते हैं। बाजार में मिलने वाले भोज्य पदार्थ स्वच्छ हों, उनमें किसी तरह की मिलावट या गंदगी न हो, यह जांचना स्थानीय प्रशासन का काम है।

सवाल सिर्फ कांवड़ श्रद्धालुओं का ही नहीं है बल्कि यह हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे शुद्ध-स्वच्छ खाना मिले। बीते कुछ सालों से राज्य सरकारें कांवड़ यात्रा में विशेष रुचि ले रही हैं, जबकि इन्हीं राज्यों में और भी तीर्थ स्थल हैं, जो बुरी तरह उपेक्षित हैं या वहां किसी तरह की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। हम सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही नहीं हैं बल्कि हमारी संस्कृति हमें सहिष्णुता व भाई-चारा भी सिखाती है।

इस तरह के आदेशों से कारोबार बाधित होता है और नीचे के वर्ग को रोजगार या दिहाड़ी से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही समाज में विभेद पैदा होगा। इस आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व गरीब दुकानदारों को होता, जो रोज कमाने-खाने वाले हैं। राज्य सरकारों को अदालत के हस्तक्षेप से पूर्व ही विचारपूर्वक निर्णय लेने की आदत डालनी होगी।

ध्रुव सर्जा स्टारर केडी-द डेविल से संजय दत्त का फर्स्ट लुक आउट

65 साल की उम्र में भी संजय दत्त की गजब फैन फॉलोइंग है। उनकी एक्टिंग आज भी उतनी दमदार है जितनी 90 के दशक में थी। इतना ही संजय दत्त की फैन फॉलोइंग समय के साथ घटी नहीं, बल्कि बढ़ी है। यही वजह है कि वो आज भी टॉप बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में गिने जाते हैं। आज एक्टर अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके चाहने वाले उन्हें इस खास दिन की बधाइयां दे रहे हैं। एक्टर ने भी अपने फैंस का पूरा ध्यान रखा है, इसलिए ही उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म केडी-द डेविल से अपना नया लुक रिवील कर दिया है। नए किरदार की उन्होंने पहली

झलक दिखाई है, जिसमें वो अजब-गजब अवतार में नजर आ रहे हैं। उनका ये लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस अपकमिंग फिल्म में संजय दत्त धाक देवा का रोल निभाएंगे। संजय दत्त की ये तस्वीर उनके जन्मदिन पर मेकर्स ने रिलीज की है और ये उनके चाहने वालों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। जैसे ही अभिनेता संजय दत्त ध्रुवा सरजा की केडी-द डेविल की एपीक दुनिया में शामिल हुए, यह फिल्म उनके खास प्रोजेक्ट्स में गिनी जाने लगी। इस पर बात करते हुए केडी-द डेविल के निर्देशक प्रेम कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त की विशालता को कौन नहीं जानता? वह कई प्रभावशाली भूमिकाओं के साथ आते हैं। उनका मुन्ना भाई आज भी बहुत सराहा जाता है, मैं बहुत आभारी और खुश हूं कि उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हां कहा और उनके साथ काम करना खुशी की बात रही।

सामने आए संजय दत्त के लुक पर आप अगर नजर डालेंगे तो एक्टर गले में बेल्ट, सिर पर टोपी और हाथ में छड़ी लिए दिख रहे हैं। इन्हें देख कर जाहिर हो रहा है कि वो एक पुलिस वाले की भूमिका में हैं, लेकिन ये पुलिस वाला कैसे होगा इसका अंदाजा लगा पाना जरा भी आसान नहीं है। सामने आई झलक में उनके बड़े बाल, दाढ़ी और माथे पर तिलक भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ बी उन्होंने लेपर्ड प्रिंट वाली शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट कैरी की है।

श्रीलंका के खिलाफ रिंकू सिंह बने फील्डर ऑफ द सीरीज

पल्लेकेले, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारतीय क्रिकेट टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में यह टीम इंडिया की पहली सीरीज जीत है। टीम ने इस दौरान कई प्रयोग किए जिसमें कुछ खिलाडियों का प्रदर्शन शानदार रहा, खास तौर पर रिंकू सिंह ने खूब सुर्खियां बटोरी। टी20 सीरीज में श्रीलंका पर 3-0 की शानदार जीत का जश्न मनाया, जिसमें कई खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें रिंकू सिंह एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे, जिन्होंने फील्डिंग में अपने असाधारण प्रयासों के लिए फील्डर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। सीरीज के रोमांचक अंतिम मैच के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पुरस्कार की घोषणा की गई। बीसीसीआई ने एक्स पर इसका एक वीडियो शेयर किया, जिसमें टीम में खुशी का माहौल साफ नजर आ रहा है। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने रवि बिश्नोई, रियान पराग और रिंकू सिंह को फील्डर ऑफ द सीरीज के लिए नॉमिनेट किया। जिसके बाद सहायक कोच रेयान टेन डेशकाटे ने अंत में रिंकू को उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया।

पेरिस ओलंपिक 2024: पीवी सिंधु की धमाकेदार जीत, राउंड ऑफ-16 के लिए किया क्वालीफाई

पेरिस, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल का अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला भी जीत लिया है।उन्होंने एस्टोनिया के क्रिस्टिन कुउबा को 21-5 और 21-10 से हरा दिया।इस जीत के साथ सिंधु ने राउंड ऑफ-16 में अपनी जगह बना ली है।बता दें कि सिंधु लगातार तीसरा पदक जीतने की ओर अग्रसर हैं। सिंधु ने मुकाबले में आसान जीत दर्ज की, पहले गेम में उन्होंने लगातार 8 प्वाइंट अपने नाम किए।

ब्रेक तक स्कोर 11-2 था। इसके बाद उन्होंने बड़ी आसानी से गेम 21-5 से अपने नाम कर लिया।दूसरे मुकाबले में कुउबा ने थोड़ा अच्छा खेल दिखाया। हालांकि, इसके बाद सिंधु ने जोरदार

वापसी की और ब्रेक तक स्कोर 11-6 कर दिया। ब्रेक के बाद कुउबा को कोई मौका ही नहीं मिला।दूसरा मुकाबला सिंधु ने 21-10 से अपने नाम किया।

पहले मुकाबले में सिंधु ने कमाल का प्रदर्शन किया था। दुनिया की 111वें नंबर की खिलाड़ी के पास उनका कोई जवाब नहीं था।पहला गेम सिंधु ने फातिमाथ नाबाह के खिलाफ सिर्फ 13 मिनट में जीता था। दूसरे गेम में 4-0 की बढ़त बनाई, लेकिन फातिमाथ ने वापसी करते हुए स्कोर 3-4 कर दिया था।भारतीय खिलाड़ी इसके बाद लगातार 6 अंक के साथ 10-3 से आगे हो गईं थी।उन्होंने मुकाबला 21-9 और 21-6 से अपने नाम किया था।

2016 में खेले गए रियो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार सिंधु ने पहली बार हिस्सा लिया था। अपने पहले संस्करण में ही उन्होंने रजत पदक हासिल किया था।

वह स्वर्ण पदक के मुकाबले में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थी। साल 2020 में उन्होंने टोक्यों ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

बॉक्स ऑफिस पर बैड न्यूज ने सेकंड वीकेड पर भी मचाया धमाल

विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं और इसकी वजह ये है कि इस जोड़ी की साथ में पहली फिल्म बैड न्यूज दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. फिल्म रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. इसी के साथ इस फिल्म ने पहले ओपनिंग वीकेंड में तो दमदार कलेक्शन किया ही था वहीं दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म ने टिकट काउंटर पर गर्दा उड़ा दिया है और खूब नोट कमा लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं ह्यबैड न्यूजह्न ने रिलीज के 10वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

बैड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये फिल्म हेटेरोपैटरनल सुपरफेकुंडेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जुड़वां बच्चे एक ही मां से पैदा होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल पिता अलग-अलग होते हैं. दिलचस्प कॉन्सेप्ट से लेकर विक्की और तृप्ति की सिज़लिंग केमिस्ट्री और फुट-टैपिंग नंबर्स तक, बैड न्यूज़ ने इन सबको लेकर खूब सुर्खी बटोरी. जिसके चलते फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी रही. इतना ही नहीं ये फिल्म विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी ओपनर है. वहीं फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर भी दमदार कमाई की थी. हालांकि पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई में गिरावट भी आई लेकिन वीकेंड पर एक बार फिर बैड न्यूज संभल गई है और इसकी कारोबार में तेजी देखने को मिली है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो बैड न्यूज ने 8.3 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई 42.85 करोड़ रुपये रही. वहीं दूसरे हफ्ते के दूसरे फ्राइडे फिल्म ने 2.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

प्रभास की द राजा साब की पहली झलक आई सामने, रोमांटिक अंदाज में दिखे प्रभास

प्रभास की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म द राजा साब से उनकी पहली झलक फिल्म मेकर्स ने रिलीज कर दी है.

मारुति द्वारा निर्देशित, हॉरर रोमांटिक कॉमेडी 10 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. द राजा साब का 45 सेकंड का टीजर प्रभास के लीड कैरेक्टर की झलक दिखाता है. क्लिप में प्रभास को मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाया गया है, जो सूट, धूप का चश्मा और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए हैं. फिल्म की पहली झलक पर फैंस ने कई तरह के रिएक्शन दिए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार जीत के बाद अब भारत की नजर वनडे सीरीज पर

पल्लेकेले, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इस मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला और इसी के साथ भारतीय टीम ने ये सीरीज 3-0 से जीती। यह गौतम गंभीर के कार्यकाल की पहली सीरीज थी। अब 2 अगस्त से वनडे सीरीज खेली जाएगी। जहां अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और वनडे कप्तान रोहित शर्मा भी टीम में वापसी करेंगे।पल्लेकेले में श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में महज 3 रन का लक्ष्य दिया था और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली गेंद पर चौका मारकर टीम को जीत दिलाई। इसी के साथ गौतम गंभीर के कार्यकाल की टी20 सीरीज जीत के साथ शानदार शुरुआत हुई। कहीं न कहीं जिस प्रेशर सिचुएशन में टीम इंडिया लडखड़ा जाती थी, गंभीर और सूर्या के

नेतृत्व में टीम ने वहां बाजी मारी।आखिरी मुकाबले में कोच गंभीर ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसकी वजह से टीम 3-0 से जीत का मौका गंवा सकती थी। भविष्य की योजनाओं और नए प्रयोग का नजारा इस मुकाबले में नजर आया। सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने भी गेंदबाजी की। दिलचस्प बात ये है कि टीम का ये प्रयोग सफल भी हुआ।पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में जीत के लिए 138 रनों का टारगेट दिया था। भारत की ओर से ओपनर शुभमन गिल ने सर्वाधिक 39 रनों की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन ही बना सका और मैच टाई हो गया।इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट वॉशिंग्टन का 17वां ओवर ही था, जिसमें उन्होंने लगातार दो गेंदों पर पहले वानिंदु हसरंगा और फिर कप्तान असलंका को पवेलियन भेजा।

एक नजर

विश्व विद्यालय को मिली डीएनवाईएस के संचालन की मान्यता

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः भाबर क्षेत्र के अंतर्गत भगवंत ग्लोबल विश्व विद्यालय को डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस (डी.एन.वाई.एस) के संचालन की मान्यता मिल गई है।विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो.पीएस राणा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग सहायक के लिए सौ सीटों की मान्यता मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा व योग भारतीय चिकित्सा की एक विधा है, जिसकी वर्तमान में बहुतउपयोगिता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। कहा कि छात्र–छात्राओं को अब विश्वविद्यालय में कंप्यूटर, प्रबंधन, विज्ञान, फार्मेसी, नर्सिंग पैराचिकित्सा के साथ ही प्राकृतिक व योग सहायक में डिप्लोमा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा।

सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े विद्यार्थी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः उमरावनगर स्थित रोहित अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदरि में अभिभावकों की गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें विद्यार्थियों को सकारात्म सोच के साथ आगे बढ़ने की सीख दी गई। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ हर्षपाल सिंह नेगी ने किया। सर्वप्रथम आचार्य अशोक ने विद्या भारती के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ ही शिक्षा क्रिएटिविटी को भी जरुरी बताया। अभिभावकों ने कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। कहा कि जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि सभी बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। कहा कि कमजोर छात्रों का टेस्ट लिया जाएगा। उन्होंने विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने का भरोसा दिया।

व्यापारियों ने की चोरों को पकड़ने की मांग

नई टिहरी। घनसाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार रात को चोरों ने तीन दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की है। घटना से व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से चोरों की पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र डंगवाल ने बताया कि बीते रात को बाजार स्थित तीन दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल और रेस्टोरेंट के ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में गुलदार की सक्रियता से छात्रों में दहशत

नई टिहरी। देवप्रयाग नगर क्षेत्र में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां स्थित संस्कृत विवि के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के सीसीटीवी फुटेज में गुलदार परिसर में चहल कदमी करता हुआ दिखाई दिया।बीते मंगलवार को जब यहां सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें गुलदार यहां अकादमिक भवन के निकट घूमता दिखाई दिया। जहां से वह रास्ता तलाश करते हुए मेन गेट की ओर जाता दिखाई दिया। मेन गेट बन्द होने पर कैंटीन की तरफ जाते दिखा। जनसंपर्क अधिकारी डॉ.वीरेंद्र वर्त्वाल ने बताया कि, सीसीटीवी फुटेज सोमवार तड़के चार बजे का है। सीसीटीवी में गुलदार के परिसर में खुले घूमते देख यहां छात्रावास में निवास करने वाले देशभर के 5 सौ छात्र, 50 छात्राएं, 25 प्राध्यापक व करीब 75 अन्य कर्मचारी दहशत से घिर गए है। इनमें से कई लोगों के परिवार में यहां साथ हैं। गुलदार के परिसर में दिखने के बाद यहा हर रात शोर शराबे के साथ ड्रम आदि बजाने को छात्र–छात्राएं मजबूर हैं।

प्रदेश सरकार मूल निवास लागू करेः नेगी

नई टिहरी। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बुधवार को कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती के चयनित अभियर्थियों के स्थाई निवास प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए हैं।

इस तरह के फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार 1950 के अनुरूप मूल निवास की व्यवस्था लागू करे। पत्रकारों से बातचीत में नेगी ने कहा कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भर्ती के मानकों को पूरा करने को फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं।

नहीं बनी सुरक्षा दीवार, नई बस्ती गिंवईस्रोत के परिवारों को खतरा

खोह नदी के तट पर रहते हैं नई बस्ती गिवईस्रोत के सैकड़ों परिवार

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः वर्षा काल में उफान पर बह रही खोह नदी ने नई बस्ती (गिवईस्रोत) के परिवारों की नींद उड़ा दी है। हालत यह है कि खोह नदी का वेग बढ़ते ही परिवारों को भू-कटाव का डर सताने लगता है। जिससे इसके आवासीय भवनों को भी खतरा बना हुआ है। पूर्व में शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम ने क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाने की सुध नहीं ली।

नई बस्ती (गिवईस्रोत) में करीब चार से पांच सौ परिवार नदी के तट पर स्थित भवनों में रहते हैं। लेकिन, वर्षाकाल में इन परिवारों को खोह नदी से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हालत यह है कि नदी का वेग बढ़ने से भू-कटाव भवनों की ओर बढ़ता जा रहा है। रात के समय वर्षा होने पर परिवारों की आंखों से नींद उड़ जाती है। दिन तो किसी तरह कट जाता है। लेकिन, रात के अंधेरे में परिवारों की निगाहे नदी के वेग पर ही टिकी रहती हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस वर्ष नदी के तट पर कई स्थानों पर सुरक्षा दीवार का निर्माण हुआ। लेकिन, उनके क्षेत्र में कोई झांकने तक भी नहीं पहुंचा। स्थिति देखकर लगता है कि सिस्टम को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जबकि, गत वर्ष खोह नदी ने लकड़ीपड़ाव, काशीरामपुर तल्ला, कुभीचौड़ क्षेत्र में खूब तांडव मचाया था।

कोटद्वार में खोह नदी के तट पर स्थित नई बस्ती (गिवईस्रोत)

झूठा निकला आश्वासन

वर्षाकाल में सुखरो नदी के तट पर रहने वाले सिम्मलचौड़ के परिवारों को भी खतरा बना हुआ है। गत वर्षाकाल में हुए नुकसान के बाद जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन, यह आश्वासन आज तक धरातल पर रंग नहीं ला पाया। नदी के वेग को बदलने के साथ ही सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए सिम्मलचौड़ वासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने तहसील में प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था। ऐसे में अब तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं होना सरकारी सिस्टम की लापरवाही को दर्शाता है।

मोटरसाइकिल की हुई भिडंत, थाने पहुंचा घायल

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः कोटद्वार शहर में बाइकर्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन बाइकर्स लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। बुधवार को तेज रफ्तार बाइक ने विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी।

दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया। घायल ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।

जानकारी के अनुसार, मो.नासीम किसी कार्य से पदमपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दूध की डेयरी के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। नासीम कुछ समय पाते इससे पहले ही वह चोटिल होकर सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचा। अस्पताल में पट्टी करवाने के बाद कोतवाली पहुंचे नासीम ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बताया कि दुर्घटना में उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूसरी बाइक को चलाने वलो नाबालिग थे। उन्हें भी दुर्घटना में चोट आई हुई है।

न्याय के लिए कोतवाली पहुंचा घायल

मजदूर संघ ने उठाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ीः उत्तराखंड जल संस्थान के तहत गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के अंशकालिक मजदूर संघ ने दैनिक वेतन, संविदा, आउटसोर्स कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग उठाई है।कहा कि संस्थान में कई पद खाली होने के बाद भी इन कार्मिकों को स्थाई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर युवाओं का नियमितीकरण करने की मांग उठाई है। सीएम को ज्ञापन भेजते हुए शाखा अध्यक्ष शिवचरण कोहली ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक निगमों, निकायों, उपकर्मों और जल संस्थान में करीब एक लाख कार्मिक दैनिक वेतन, संविदा, विशेष श्रेणी, अंशकालिक, पीटीसी, आउटसोर्स पर कार्य कर रहे हैं। कहा कि संस्थान के विभिन्न उपक्रमों में हजारों पद खाली हैं। जिनके सापेक्ष संविदा कार्मिक कार्य कर रहे हैं। कहा कि नियमितीकरण की प्रतीक्षा में कई कार्मिक दैनिक वेतन पर ही सेवानिवृत्त हो गए। जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने सीएम से ऐसे कर्मियों को नियमित करने की मांग उठाई है। कहा कि राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के आह्वान पर 17 अगस्त से देहरादून, हल्द्वानी, टनकपुर, टिहरी के कर्मचारी एक दिवसीय धरना–प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो सचिवालय कूच व रैली के साथ ही कार्य बहिष्कार व उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर जल्द करें काम

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ीः नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति ने बुधवार को आयुक्त गढ़वाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम घोषणाओं पर जल्द काम शुरू करने की मांग उठाई। आयुक्त से मुलाकात करते हुए समिति के पदाधिकारियों ने रांसी स्टेडियम के पास निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने, राजकीय पॉलीटेक्निक का कार्य जल्द पूरा किए जाने, पुराने जेल परिसर में राजकीय संग्रहालय की स्थापना करने, ल्वाली झील में हुए कायी की जांच करवाते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा करने, एनसीसी अकादमी की स्थापना करने सहित लंबित सीएम घोषणाओं का कार्य जल्द पूरा करने की मांग उठाई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, सचिव गबर सिंह नेगी, केदार सिंह गुसांई, अनीता रावत, व्योमेश जुगराण, प्रशांत नेगी, ठाकुर सिंह नेगी आदि शामिल रहे।

निश्चेतक की तैनाती नहीं होने पर भड़की युवा कांग्रेस

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में निश्चेतक की तैनाती नहीं होने पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि निश्चेतक नहीं होने के कारण मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। यदि जल्द निश्चेतक की तैनाती नहीं की गई तो युवा कांग्रेस आमजन के साथ मिलकर आंदोलन चलाएगी।

बुधवार को कार्यकर्ता व पदाधिकारी राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने प्रमुख अधीक्षक के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन भेजा।

बताया कि राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में दूर-दराज से मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। लेकिन, एक माह से अधिक का समय हो चुका है निश्चेतक चिकित्सक के सेवानिवृत्त होने के बाद भी दोबारा निश्चेतक की तैनाती नहीं की गई है। जिसके कारण हास्पिटल में मरीजों के आपरेशन नहीं हो पा रहे है। कहा कि राजकीय बेस हास्पिटल में शीघ्र ही बेहोशी के चिकित्सक की नियुक्ति की जाए, अन्यथा उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश घिल्डियाल, बाबी बिष्ट, मनीष चातुरी, अंकित, अनूप गुसांई, आमिर मौजूद रहे।

अस्पताल में प्रमुख अधीक्षक के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र भेजते सदस्य

अशोक रावत बने राइका पुरियाडांग के पीटीए अध्यक्ष

आयोजित बैठक में भाग लेते सदस्य

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः विकास खंड कल्जीखाल के राइका पुरियाडांग में पीटीए संघ की नवीन कार्यकारणी गठित की गई। इस दौरान अशोक रावत को पीटीए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई।

निवर्तमान पीटीए अध्यक्ष महाकान्त नैथानी की अध्यक्षता में विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघ की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार घुनियाल द्वारा बैठक में उपस्थित लोगों का स्वागत किया गया। बैठक में पिछली कार्यकारणी की कार्यवाही को रखते हुए महाकान्त नैथानी द्वारा कार्यकारिणी को भंग किया गया। प्रधानाचार्य मनोज घुनियाल द्वारा विद्यालय का गत वर्ष परीक्षाफल अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्यालय में कुल स्वीकृत पद, कार्यरत पदों का विवरण एवं साथ वर्ष में प्राप्त आय, व्यय को सम्पूर्ण विवरण बैठक में प्रस्तुत किया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं से अभिभावकों को अवगत कराया गया। इस दौरान अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर अशोक रावत, उपाध्यक्ष पदेन मनोज कुमार धुनियान (प्रधानाचार्य), कोषाध्यक्ष मनोज नैथानी, सचिव चन्द्र वीर सिंह रावत, अध्यापक सदस्य रीना नेगी, बालम सिंह राणा, संरक्षक सुरेन्द्र सिंह नेगी। सदस्य देवेन्द्र सिंह पवार, सुभाष चन्द्र, सुषमा देवी सैनार,रेखा देवी बुटली, ज्योति देवी नैथाना, आशा देवी नैथाना को चुना गया। इस मौके पर जगमोहन डांगी, भगवती प्रसाद शैलवाल, को सक्रिय सदस्य बनाया गया। बैठक का संचालन शिक्षक राकेश भारती ने किया।

एनआईटी का मुख्य कार्य हो प्रारंभ

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ीः सुमाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जहां पर पूर्व में दो बार शिलान्यास हुआ है वही से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान(एनआईटी) का मुख्य कार्य शुरू किए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को सुमाड़ी गांव से आए प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त गढ़वाल से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं के हल की मांग उठाई।आयुक्त गढ़वाल से मुलाकात के दौरान सुमाड़ी गांव से आए प्रतिनिधिमंडल में शामिल ग्रामीण राजमोहन चमोली, विपुल जोशी आदि ने निर्माणाधीन परिसर में भूमिधारकों के अधिकारों के हक-हकूको को संरक्षित करने की मांग उठाई। कहा कि सुमाड़ी गांव के ग्रामीणों ने रोजगार के साधनों व पलायन पर रोकथाम के लिए अपनी भूमि को देशहित में दान कर स्वयं को भूमिहीन कर दिया। संस्थान ने यहां पर सैकड़ों पेड़ों का कटान भी कर दिया लेकिन अब संस्थान द्वारा अंतिम सर्वे के बाद दो बार शिलान्यास हो चुके स्थान के बजाए करीब साढ़े 4 किलोमीटर दूर से निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है।

चंद्रप्रकाश जखमोला बने अध्यक्ष

आयोजित बैठक में भाग लेते शिक्षक व अभिभावक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः शहीद लांस नायक धनवीर सिंह राणा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कण्वघाटी में शिक्षक-अभिभावक संघ की नवीन कार्यकारणी का गठन किया गया। इस दौरान चंद्रप्रकाश जखमोला का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई।

बुधवार को सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में चंद्रप्रकाश जखमोला को अध्यक्ष व उषा रावत को सचिव चुना गया। अन्य पदाधिकारियों में ममता तिवारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। पूनम देवी व यतेंद्र सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया।

प्रधानाचार्य पुष्पा धस्माना ने कहा कि विद्यालय के विकास में अभिभावकों, शिक्षकों दोनों का ही सहयोग आवश्यक है। तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्होंने विद्यालयों में अभिभावकों की उदासीनता पर भी चिंता व्यक्त की। कहा कि विद्यालय में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिभावकों को भी सहयोग करना चाहिए।

इस मौके पर किरन जगरवाल, अर्चना कंडवाल, भावना पांडे, दिव्या, प्रियंका विद्यार्थी, कलावती, अलका लिंगवाल मौजूद रहे।

पीआरडी के जवानों की समस्याओं का करें निराकरण

जयन्त प्रतिनिधि।पौड़ीः पीआरडी हित संगठन ने 2021 तक के प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को ही पूरे सालभर नियमित रोजगार देने, प्रशिक्षित जवानों की मूलभूत समस्याओं का शासनादेश जारी करने व 2021 तक के प्रशिक्षित जवानों को ही प्रविष्ट नंबर जारी करने की मांग की है। संगठन ने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर जल्द ही समस्याएं हल करने की मांग उठाई है। संगठन ने डीएम के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा।

संगठन के जिलाध्यक्ष ललित सिंह, संपूर्ण सिंह ने कहा कि सरकार ने अप्रशिक्षित लोगों से पीआरडी कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने के आदेश जारी किए हैं जो कि सभी 2021 तक के प्रशिक्षित पीआरडी जवानों के साथ न्यायोचित नहीं है। आरोप लगाया कि पीआरडी जवानों की आपत्ति के बाद भी शासन ने पीआरडी ऐक्ट 1948 में संशोधन किया गया, जिससे पीआरडी जवानों में नाराजगी बनी हुई है। उन्होंने साल 2021 तक के प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को ही पूरे सालभर नियमित रोजगार देने, प्रशिक्षित जवानों की मूलभूत समस्याओं का शासनादेश जारी करने व 2021 तक के प्रशिक्षित जवानों को ही प्रविष्ट नंबर जारी करने की मांग की है।

आयुक्त गढ़वाल ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ीः आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बुधवार को जिला चिकित्सालय, गैस गोदाम और नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने इंटररनेट कनेक्टीविटी सुचारु कराने, इंडेन गैस गोदाम में अग्निशमन यंत्रों की निष्क्रियता को लेकर एमडी जीएमवीएन को सेप्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए।

बुधवार को जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए पाया गया कि मेडिकल स्टोर में इंटरनेट की असुविधा के चलते दवाओं के स्टॉक का ऑनलाइन नहीं हो पाया है, आयुक्त ने सीएमओ व महंत इंदिरेश शाखा पौड़ी को इंटरनेट सुविधा सुधारने के निर्देश दिए। क्षय नियंत्रण केंद्र में मरीजों के आंकडों में अशुद्धियां व विरोधाभास होने पर उन्होंने जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी को स्पष्ट आंकड़े दर्ज करने को कहा।

इस दौरान कुछ तीमारदारों ने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किए जाने की मांग आयुक्त से की। इंडेन गैस गोदाम के निरीक्षण के दौरान गोदाम में लगे अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय अवस्था में पाए गए, आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए गढ़वाल मंडल के सभी गैस गोदामों, पेट्रोल पम्पों व टूरिस्ट गेस्ट हाउसों का एक हफ्ते के भीतर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश जीएमवीएन के एमडी को निर्देश दिए। नगर पालिका पौड़ी का निरीक्षण करते हुए प्रशासक को शहर में साफ–सफाई चाक–चौबंध रखने, शहर की सभी स्ट्रीट लाईट को दुरस्थ रखने, रास्तों में ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम डा. आशीष चौहान, अपर आयुक्त नरेंद्र, सीएमओ डा. प्रवीण कुमार आदि शामिल रहे।

।। कार्यालय :- नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) ।।

पत्रांक :- 1237 /कर अनु0/भव0ना0/2024-25 दिनांक :- 29.07.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा नगर निगम कोटद्वार के भवन कर अभिलेखों पूर्व भवन स्वामी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करने हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्रों एवं शपथ पत्र आदि के आधार पर आवेदन किया गया है।

अतः नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 213(ख) के अन्तर्गत समस्त प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को निम्न नामान्तरण/नामान्तरणों पर आपत्ति हो वह मय साक्ष्यों को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मियाद समाप्त होने पर उपलब्ध अभिलेखिया साक्ष्यों के आधार पर सम्पत्ति के नामान्तरण हेतु निर्णय पारित कर लिये जायेंगें।

क्र0 सं0	सम्पत्ति संख्या एवं मौहल्ले/वार्ड का नाम	भवन कर अभिलेखों में दर्ज नाम (नाम जो निरस्त होना है)	आवेदक का नाम व पता (नाम जो दर्ज होना है)	सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का आधार
1	2	3	4	5
1	32/28/15 स्टेशन रोड	श्री जयजीत बडथवाल पुत्र स्व0 सन्तन बडथवाल (115 वर्गफुट यानि10.68 वर्गफुट)	श्री प्रशान्त भाटिया पुत्र नरेश भाटिया (115 वर्गफुट यानि 10.68 वर्गफुट)	रजिस्ट्री एंव शपथ पत्र

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार।
(0318/51)

विद्यार्थियों ने किया पौधा रोपण, संरक्षण का लिया संकल्प

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने लगाए गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में अशोक, सिल्वरओक, कनेर सहित अनेक प्रजाति के पौधों का रोपण किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ रोशनी असवाल ने पौधों के जीवन के लिए आवश्यक घटक जल के संरक्षण के लिए स्वयंसेवियों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बरसात के इस सीजन में हमें अधिक से अधिक जल संरक्षण करना चाहिए। संपूर्ण जीव जगत का जीवन यापन जल से ही संभव है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ संजीव कुमार ने स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि पौधे लगाने के साथ-साथ यथासंभव उनका बचाव कार्य भी करना चाहिए। हम अपने छोटे-छोटे प्रयासों से निश्चित ही एक दिन इस वसुंधरा को हरा भरा कर देंगे। इस अवसर पर डॉ विनोद भण्डारी, डॉ संदीप कुमार, वीरेंद्र सैनी, जितेंद्र कुमार, लीला देवी, अभिषेक नेगी, सौरभ, ज्योति, पायल, दीपक, बादल,आदि अनेक स्वयंसेवी उपस्थित थे।

उत्तर रेलवे

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियन्ता/II/मुरादाबाद द्वारा ई–टेन्डर निम्न टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेन्डर संख्या दिनांक	93-DRM-MB-2024-25 Date 30.07.2024	94-DRM-MB-2024-25 Date 30.07.2024
कार्य का नाम	Miscellaneous works in connection with track maintenance in the section of SSE/P/SFPR under ADEN/II/HRI.	Replacement of girder bridges, Bridge no. 17(1x7.92m), 25(1x7.92m) in BLM-SPC section & 73(3x9.14m) in ON-BLM section by PSC Slab in the section of Sr.DEN/II/MB.
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक/समय	23.08.2024, 16:00	23.08.2024, 16:00
अनुमानित लागत	79,99,971.06	1,18,46,421.81
धरोहर राशि	1,60,000.00	2,09,200.00
बिडिंग स्टार्ट तिथि	09.08.2024	09.08.2024
आफर की वैधता	60 दिन	60 दिन
कार्य पूर्ण करने की अवधि	12 माह	06 माह

सं.: 74-W/2/3/WA/Publication दिनांक: 30.07.2024 2333/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एक नजर

बगैर मान्यता के स्कूलों पर कार्यवाही की मांग

नई टिहरी। नरेंद्रनगर के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी और पर्यावरणविद विजय जड़धारी ने बताया कि नरेंद्रनगर और चंबा क्षेत्र की एक पब्लिक स्कूल बीते कई वर्षों से बगैर मान्यता के संचालित की जा रही थी। जिस कारण छात्र–छात्राओं और अभिभावकों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। वन मंत्री सुबोध उनियाल के संज्ञान में प्रकरण आने के बाद बीते दिनों शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल की मान्यता खत्म कर दी थी। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन ने बगैर मान्यता के स्कूल का संचालन जारी रखा। उधर, डीईओ बेसिक वीके ढौंडियाल ने बताया कि स्बंधित पब्लिक स्कूल संचालक को आरटीई का उल्लंघन करने और मानकों की अनदेखी के लिए बंद करने का नोटिस दिया गया है। आगे की कार्रवाई अब सीईओ कार्यालय स्तर से होनी है।

एआई तकनीकी का मानव कल्याण में हो उपयोग

नई टिहरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन विषय को लेकर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में जिला स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। विषय विशेषज्ञों ने कहा कि एआई तकनीक, भविष्य की संभावनाएं और मानव जाति के कल्याण के लिए एआई की महत्ता की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि एआई इंसानों की अक्ल की नकल करने का बेहतर माध्यम है।मंगलवार को आयोजित सेमिनार का डायट नई टिहरी में निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल, प्राचार्य हेमलता भट्ट, सीपी रतूड़ी, एससीईआरटी के उप निदेशक डॉ. कष्णानंद बिजल्वाण, डॉ. राकेश गैरोला, डॉ. रंजन भट्ट, शुभ्रा सिंघल ने संयुक्त रूप से शुभारंभ करते हुए एआई को लेकर भविष्य की चुनौती की जानकारी दी। कार्यक्रम समन्वयक सरिता असवाल, सह समन्वयक संजीव भट्ट ने बताया कि जिलेभर से 160 प्रवक्ता, एलटी शिक्षक और डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने सेमिनार में प्रतिभाग किया।

हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर कार्यशाला में दिया जोर

नई टिहरी। सरस्वती शिशु मंदिर जे ब्लॉक में हिंदी विषय के आचार्य प्रशिक्षण कार्यशाला में संकुल क्षेत्र के शिशु मंदिरों के भाषा विषय के शिक्षकों को हिंदी की महत्ता, राष्ट्र भाषा को प्रोत्साहन करने और हिंदी में कार्य करने की आवश्यकता की जानकारी दी गई। बुधवार को शिशु मंदिर जे ब्लॉक में कार्यशाला का शिशु भारती के जिला निरीक्षक राकेश बहुगुणा और आरएसएस के विभाग प्रचारक पारस ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शिशु और विद्या भारती के स्कूल छात्रों को गुणवत्तापरक और संस्कारवान शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों के शिक्षकों पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने का ज्यादा भार है। कहा कि हिंदी में कार्य करना आसान है। लेकिन हमें अपने से ही शुरुआत करनी होगी। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है, जब वहां मातृ और राष्ट्र भाषा का धारा–प्रवाह, कार्य करने की सर्वानुमति हो। हम पश्चिमी देशों की नकल जरूर करते हैं। लेकिन हमारे देश में यदि कोई हिंदी में बोलता, कार्य करता है तो उसे हीन भावना से कुछ लोग देखते हैं। ऐसे में सभी शिक्षकों को मिलकर हिंदी विषय को रूचिकर तरीके से छात्रों को पढ़ाना होगा। इस मौके पर आरएसएस के जिला प्रचारक दीपक, प्रधानाचार्य अनिल उनियाल, शीशराम कोठियाल, भगत सिंह भंडारी मौजूद रहे।

नई टिहरी में मेडिकल कालेज बनने का रास्ता साफ

नई टिहरी। टिहरी बांध विस्थापित नई टिहरी शहर में मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय के निकट टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड मेडिकल कॉलेज बनाएगा। जिसके लिए बुधवार को विधायक किशोर उपाध्याय की मौजूदगी में आयोजित बैठक में इस बावत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। विधायक किशोर ने मेडिकल कालेज बनाने की स्वीकृति को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार भी जताया।जिला सभागार में आयोजित बैठक में विधायक ने बताया कि मेडिकल कालेज के लिए राज्य सरकार 5 हेक्टेयर और अवशेष 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि टीएचडीसी उपलब्ध कराएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से टिहरी ही नहीं बल्कि उत्तरकाशी, देवप्रयाग से लगे पौड़ी जिले के निवासियों को लाभ होगा। इससे टिहरी के विकास को नए पंख भी लगेंगे। बीते दिनों टिहरी बांध के भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के प्रस्ताव पर टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए टीएचडीसी को निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन के सफल क्रियान्वयन को लेकर सीडीओ ने ली बैठक

चमोली। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला स्तरी पर्यवेक्षण समिति की बैठक हुई। जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया हेतु तिथि निर्धारित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ प्रतिभावान खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाए। प्रत्येक ब्लाक एवं नगर पालिका में खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक करते हुए स्थान चयन किया जाए। शिक्षा, युवा कल्याण, जल संस्थान, नगर पालिका और चिकित्सा विभाग प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु क्रीडा विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करें।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्तर पर 23 एवं 24 अगस्त को और विकासखंड स्तर पर 27 एवं 28 अगस्त 2024 को चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जनपद स्तर पर 31 अगस्त से 17 सितंबर 2024 तक स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर 14 से 23 वर्ष के 100 बालक एवं 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। योजना के तहत 14–17 आयु वर्ग, 17–19 आयु वर्ग, 19–21 आयु वर्ग और 21–23 आयु वर्ग में कुल 12 खेलों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक आयु वर्ग में 25 बालक एवं 25 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को एक वर्ष तक रु.2000/प्रतिमाह छात्रवृत्ति और खेल उपकरण किट के लिए 10 हजार रुपये की धनराशि एक मुश्त प्रदान की जाएगी।जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, बैडमिंटन, ताईक्वांडों, बॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, कबड्डी खेलों में प्रत्येक आयु वर्ग और प्रत्येक खेल में दो–दो खिलाड़ी और एथलेटिक्स में प्रत्येक आयु वर्ग में तीन–तीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

गुलदार प्रभावित क्षेत्र में झाड़ियां काटी

नई टिहरी। मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग ने माणिकनाथ रेंज में अभियान शुरू किया है। जिसमें आरआरटी, क्यूआरटी व वन कर्मियों की संयुक्त टीम दिन रात प्रभावी गश्त व जनसम्पर्क कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभाग ने गुलदार प्रभावित संवेदनशील स्थलों में फॉक्स लाइट तथा एक दर्जन से अधिक कैमरा ट्रैप लगाये गये हैं। रेंजर माणिकनाथ मदन सिंह रावत ने बताया कि, देवप्रयाग में 18 जुलाई को हुई मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटना के बाद घटनास्थल एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में वन विभाग ने अभियान शुरु किया हैं। देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत घटनास्थल वाले रास्ते सहित आबादी के समीप वन क्षेत्रों में उगी झाड़ियों का कटान किया जा रहा है। इससे गुलदार को आबादी क्षेत्र के निकट छिपने का स्थान नही मिल सकेगा। साथ ही आम लोगों को आवाजाही में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्षेत्र में एक दर्जन अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती गश्त के लिए की गयी है, जिसमें नरेन्द्रनगर वन प्रभाग का अन्य रेंजों का स्टाफ भी शामिल है। विभिन्न जगहों पर गश्त कर रही टीमों का वन क्षेत्राधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे है। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर अभियान पर नजर बनाये हुये है। जन–जागरूक को लेकर लोगों में पम्पलेट बांटे जा रहे है। संवेदनशील क्षेत्रों में पोस्टर, बैनर तथा साईन बोर्ड लगाये गये हैं एवं गुलदार को भगाने के लिए पटाखे भी बांटे गये हैं।

वन विभाग ने क्षेत्र के भट्टगांव, टुण्डरियाल काण्डा, मुल्यागांव, हिण्डोलाखाल, गोसिल, पाली, पलेठी आदि गोंवों में अभियान चलाया जा रहा है।

सिमली महिला बेस अस्पताल को प्रारंभ करने के लिए जुटा रहे सर्मथन

चमोली। सिमली महिला बेस अस्पताल का संचालन प्रारंभ करने के लिए संघर्ष समिति के सदस्यों ने गैरसैंण, मेहलचौरी व्यापार संघ तथा राजकीय पीजी कॉलेज गैरसैंण के छात्र संघ से वार्ता कर समर्थन जुटाया।

सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र नेगी ने बताया कि सरकार ने करोड़ों की राशि से वर्ष 2012 में सिमली में महिला बेस अस्पताल का निर्माण प्रारंभ कराया। अस्पताल का संचालन अब तक न किए जाने से जनपद के जरूरतमंद मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बताया कि व्यापार संघ गैरसैंण के अध्यक्ष सुरेन्द्र बिष्ट, मेहलचौरी व्यापार संघ के अध्यक्ष मोहन नेगी, राजकीय पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश खत्री, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के गढ़वाल मंडल प्रभारी सुरेश बिष्ट सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी 200 बेड के अस्पताल का संचालन प्रारंभ करने में सहयोग देने का भरोसा दिया है।

बाइक की टक्कर में युवक घायल

श्रीनगर गढ़वाल।श्रीनगर चारधाम यात्रा पर जा रहे कांवड़ियों की तेज रफ्तार बाइक ने एक बाइक सवार युवकों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसमें से एक गंभीर घायल युवक को एम्स रेफर किया गया है, जबकि एक का इलाज संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़वाल विवि के छात्र कैवल्य जखमोला अपने घर भक्तियाना से गढ़वाल विवि की ओर आ रहे थे, तभी कांवड़ियों की तेज रफ्तार बाइक पौड़ी चुंगी के सामने बाइक पर पीछे से टक्कर मारकर फरार हो गई। मामले की सूचना सूचना अन्य छात्रों पता लगने के बाद मौके पर पहुंचे छात्रों ने कांवड़ियों को रोका तो तभी कांवड़ियों ने उन पर हाथापाई करना शुरू कर दिया और बाइक की चाबियां लेकर फरार हो गये। जिसके बाद गढ़वाल विवि के छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल के नेतृत्व में छात्रों नें कोतवाली पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करने, कांवड़ियों की तेज रफ्तार एवं साइलेसरों की आवाजों पर अंकुश न लगाये जाने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर जा रहे कांवड़िये तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं ला पा रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक होशियार सिंह पंखोली ने बताया कि आरोपी कांवड़िये को देवप्रयाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि घायल की सर पर गंभीर चोट लगने के कारण एयर लिफ्ट किया जाना था, लेकिन मौसम में विजिबिलटी न होने कारण घायल को एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है।

उमस भरी गर्मी से लोग परेशान

श्रीनगर गढ़वाल। उमस भरी गर्मी से श्रीनगर में आमजन परेशान हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत बुधवार को जनपद में भारी बारिश की संभावनाएं जताई थी, लेकिन श्रीनगर में बीते एक माह से ठीक से बारिश न होने से आम जनमानस उमस भरी गर्मी से बेहाल है।

आसमान में बादल के साथ–साथ धूप की तपिश के बीच गर्मी बढ़ी है। गढ़वाल विवि के भौतिकी विभाग के हिमालयन वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के प्रभारी आलोक सागर गौतम ने बताया कि अत्यधिक वाहनों के चलने से श्रीनगर में लगातार वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जिससे वातावरण में धूल के कण ज्यादा होने के कारण उष्म ज्यादा अवशोषित कर रहे हैं। जिससे वातावरण में नमी के कारण लगातार गर्मी बढ़ रही है।

आरक्षित सीटों को सामान्य करने के मामले पर छात्रों का धरना जारी

श्रीनगर गढ़वाल। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आरक्षित सीटों को सामान्य करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर एबीवीपी व आर्यन संगठन से जुड़े छात्र गत पांच दिनों से विवि प्रशासन से रोस्टर दिखाने की मांग पर अड्डे हुए हैं। मंगलवार देर सांय तक छात्रों व अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान न निकलने पर छात्र रात भर कुलसचिव कार्यालय में बैठे रहे। बुधवार को छात्रों का धरना कुलसचिव कार्यालय में जारी रहा। इस बीच कुलसचिव के कार्यालय में न पहुंचने पर आक्रोशित छात्रों ने विवि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलसचिव की कुर्सी पर गुमशुदा का पोस्टर चस्पा कर दिया।

कुछ देर बाद जब छात्र कार्यालय से बाहर निकले तो यहां ताला लगा दिया गया। जिससे छात्र और आग बबूला हो गये। आक्रोशित छात्रों ने विवि प्रशासनिक भवन गेट के समीप धरना शुरू कर दिया। एबीवीपी के अमन पंत ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

बिना रोस्टर के आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग में कर दिया गया है,जब विवि से इस संबंध में रोस्टर मांगा जा रहा है तो अधिकारी रोस्टर दिखा नहीं पा रहे हैं। छात्र नेता आकाश रतूड़ी, दिपांशु मलवाल और रोबिन असवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया हमेशा से छात्रों के प्रति नकारात्मक रहा है, छात्रों को छोटे से काम से लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। परीक्षा परिणामों के घोषित होने में देरी होती है, जिससे छात्रों को काफी नुकसान होता है।मौके पर केशव गुसांई, जसवंत राणा, साहिल, आशु पंत, सौरभ, सारांश आदि मौजूद रहे।

गढ़वाल विवि का प्रशासनिक भवन अग्रिम आदेशों तक बंद

श्रीनगर गढ़वाल। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए गढ़वाल विवि प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक विवि प्रशासनिक भवन को बंद करने के आदेश जारी किये हैं। गढ़वाल विवि के कुलसचिव प्रो. एनएस पंवार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि विवि प्रशासनिक भवन में कतिपय समूहों द्वारा उत्पन्न अराजक परिस्थितियों, भय एवं अशांति के वातावरण और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए गढ़वाल विवि ने प्रशासनिक भवन अग्रिम आदेशों तक बंद किए जाने का निर्णय लिया है। कहा कि सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारी दूरभाष एवं ऑनलाइन माध्यम से अपने नियंत्रक अधिकारियों को अपने नियमित कार्य दायित्व का निर्वहन के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गये हैं।

मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती मनाई

चमोली। राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के हिंदी विभाग द्वारा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रतिभा आर्य की अध्यक्षता में प्रेमचंद की 144 वीं जयंती मनाई गई। डॉ. पुष्पा रानी द्वारा मंच संचालन किया गया।

इतिहास विभाग से अनुन कुमार द्वारा प्रेमचंद के जन्म स्थान लमही व गोदान उपन्यास पर अपने विचार रखें। समाज शास्त्र विभाग से मोहित उप्रेती ने प्रेमचंद की पत्रविधा पर प्रकाश डाला।

राहत कार्य शुरू न होने पर पंती के ग्रामीणों का प्रदर्शन

चमोली। भारी बारिश के कारण पंती गांव के कई मकानों मे मलबा आने और गांव को हो रहे खतरे को देखते हुए और आपदा के पांच दिनों बाद भी क्षेत्रीय विधायक और उच्च अधिकारियों के आपदाग्रस्त क्षेत्र में ना पहुंचने पर ग्रामीणों में बुधवार को प्रदर्शन किया।बुधवार को ही ब्रिडकुल के अधिशासी अभियंता नरेश कुमार और तहसीलदार नारायणबगड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को पंती गधेरे के मलबे को साफ करने सड़क को दुरुस्त करने का आश्वाशन दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बुटोला ने पंती हंसकोटी मोटर मार्ग की जांच किए जाने के साथ गधेरे के मलबे को साफ करने की बात कही। मौके पर थराली विधायक के ना पहुंचने पर रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई।

उत्तराखंड के लिए आपदा मुआवजा राशि बढ़ाई जाए : महेंद्र भट्ट

देहरादून। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में चर्चा के दौरान बुधवार को उत्तराखंड के लिए आपदा राहत राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए राज्य को मानकों में बदलाव का अधिकार भी दिया जाए।राज्यसभा में बोलते हुए भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड एवं अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए आपदा मुआवजा राशि बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में होने वाली क्षति पर मिलने वाली प्रतिपूर्ति की राशि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि राज्य में बार बार आपदा आने के कारण लोगों को विस्थापित करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आपदा में क्षतिपूर्ति दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को इससे न्यायोचित आर्थिक राशि नहीं मिल पाती।

उत्तराखण्ड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के सदस्यों ने की सीएम धामी से भेंट

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के सदस्यों ने भेंट की। उन्होंने एक राज्य एक पंचायत चुनाव से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित जिला पंचायत अध्यक्ष संगठन, जिला पंचायत सदस्य संगठन तथा ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बागेश्वर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे का विरोध

देहरादून। बागेश्वर में छात्र गुटों के बीच हुए विवाद में केवल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे का संगठन ने विरोध किया है। बुधवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय में एडीजी एपी अंशुमान को ज्ञापन दिया। जिसमे पुलिस पर सरकार के दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया। विकास नेगी ने आरोप लगाया कि 29 जुलाई को राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर में एबीवीवीपी छात्र संगठन ने बिना महाविद्यालय प्रशासन की अनुमति के महाविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित कराया। राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष कमलेश गडिया ने महाविद्यालय में बिना अनुमति के कराये जा रहे इस कार्यक्रम का विरोध किया। आरोप है कि इस पर कुछ छात्रों ने उनसे मारपीट की। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई के बजाए पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और एओ बागेश्वर को हटाया जाए। इसके अलावा एनएसयूआई की ओर से दी गई तहरीर पर तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कैतूरा, सुधांशु अग्रवाल, सागर सेमवाल, मुकेश बसेरा, प्रांचाल नौनी,हरजोत सिंह, पुनीत राज और अभिनव सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ओवरसीज बैंक की बंधक संपत्ति पर कब्जा

देहरादून। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कनखल, हरिद्वार बंधक औद्योगिक संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बैंक के विधि अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत को नजर अंदाज कर दिया। इसके बाद बैंक की ओर से एसएसपी से शिकायत की गई। जिस पर हरिद्वार एसएसपी ने थाना प्रभारी को संपत्ति पर फिर से बैंक का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। बैंक ने स्थानी पुलिस थाने की भूमिका को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। बैंक की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से सरकारी संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जे में रखा गया और शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिली चार फैकल्टी

देहरादून। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संविदा के आधार पर मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही है।

इसी क्रम में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाल राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर में राज्य सरकार ने विभिन्न संकायों के अंतर्गत चार मेडिकल फैकल्टी तथा दो कैज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। नई मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति से जहां मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी दूर होगी वहीं शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार आयेगा। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार/चयन समिति द्वारा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न संकायों में रिक्त मेडिकल फैकल्टी के पदों के लिये साक्षात्कार आयोजित किया गया। जिसमें चयन कमेटी ने चार मेडिकल फैकल्टी तथा दो कैज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर का चयन किया। जिसमें पैथोलॉली विभाग के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफसर के पद पर डॉ पवन भट, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉ. स्वाती पुण्डीर, आर्थोपेडिक्स में डॉ. वेद प्रकाश अग्रवाल, ईएनटी में डॉ. श्वेता पूरबी का चयन किया गया। इसी प्रकार कैज्युअल्टी मेडिकल विभाग में कैज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद पर डॉ. अजीत कुमार तथा डॉ. कृष्णाकांत त्यागी का चयन किया गया है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है।

चयनित मेडिकल फैकल्टी एवं कैज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर को तीन वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिये नियुक्त किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति के लिये सरकार लगातार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री धामी ने की पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पशुपालन और डेरी विकास के क्षेत्र में आगामी 03 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में योगदान 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 05 प्रतिशत करने की दिशा में कार्य किये जाएं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय उत्पादों को तेजी से बढ़ावा दिये जाने पर भी बल दिया। उन्होंने पशुपालन और डेरी विकास के क्षेत्र में जीएसडीपी में वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधनों का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के साथ प्रत्येक जनपद में एक–एक मॉडल पशु चिकित्सालय बनाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ नवाचार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में वृद्धि हो और पलायन भी रूके। डेरी विकास तथा पशुपालन के क्षेत्र में राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिये अन्य प्रदेशों से आयातित दूध व दुग्ध उत्पादों, पोलट्री उत्पादों की निर्भरता को कम किया जाए।

गोट वैली, कुक्कुट वैली और ब्रायलर फार्म की स्थापना राज्य में पशुपालकों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजनाओं को और तेजी से बढ़ावा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेरी विकास के लिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ ही विभिन्न दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। दुग्ध उत्पादन से लाभकारी आय के लिए इनपुट प्रोडक्सन एवं डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाए। एफ.पी.ओ के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के चारा बीज उपलब्ध कराने और हरा एवं सूखा चारा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किये जाने के साथ राज्य में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।

राज्य में मछली की खपत के अनुरूप हो उत्पादन : मुख्यमंत्री

मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फिश के उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। इनकी बिक्री के लिए भी उचित प्रबंध किये जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। राज्य में मत्स्य पालन को और तेजी से बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य तय किये जाएं, लक्ष्यों को फोकस करते हुए समयबद्धता के साथ आगे कार्य किये जाएं। राज्य में मछली की खपत के अनुरूप उत्पादन हो इस दिशा में भी तेजी से प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से भी अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों के निर्माण से उनमें मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहीं जल संरक्षण की दिशा में भी यह सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कलस्टर बनाकर तालाबों का निर्माण किया जाए और उनके माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com